पहले: वी. रामास्वामी, सीजे और जी.आर. मजीठिया। जे.

हरियाणा राज्य और अन्य,-अपीलकर्ता।

बनाम

करतार सिंह और अन्य,-प्रतिवादी।

1986 का पत्र पेटेंट अपील संख्या 832. 16 सितंबर, 1988।

पंजाब नगरपालिका अधिनियम (1911 का III) - धारा 3(18) (बी) - हरियाणा नगरपालिका अधिनियम (1973 का XXIV) - धारा 203 से 210 - पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम (1963 का एक्सएलआई) - धारा 4(1)(बी)-सरकार धारा 3(18)(बी) के तहत नगरपालिका सीमा के भीतर के क्षेत्र को 'अनिर्मित क्षेत्र' के रूप में अधिसूचित कर रही है-हरियाणा अधिनियम की धारा 203 के तहत बनाई गई टाउन प्लानिंग योजना के निर्माण के लिए अनुरोध-इसके बाद सरकार इसे अधिसूचित करेगी अनुसूचित सड़क अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के तहत 'नियंत्रित क्षेत्र' के समान क्षेत्र - ऐसी अधिसूचना - क्या नगर नियोजन योजना के निर्माण और उसके कार्यान्वयन पर रोक है - धारा 203 - क्या अनुसूचित सड़क अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है - हरियाणा अधिनियम और अनुसूचित सड़क अधिनियम-क्या कब्जे अलग-अलग हैं

किराये के क्षेत्र-नगर नियोजन योजना तैयार करने की सरकार की शक्ति-चाहे अनुसूचित सड़क अधिनियम द्वारा छीन ली गई हो।

माना गया कि पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 की धारा 24 की स्पष्ट व्याख्या अन्य अधिनियमों के तहत तैयार नियंत्रित क्षेत्र में शामिल भूमि के विकास के लिए विकास योजनाओं की सुरक्षा करती है। अनुसूचित सड़क अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) में परिकल्पना की गई है कि यह किसी अन्य के तहत की गई कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगी।

अधिनियम, सिवाय इसके कि जहां अन्य अधिनियम के तहत की गई कार्रवाइयां अनुसूचित सड़क अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत हैं। अनुसूचित सड़क अधिनियम के प्रावधान विभिन्न क्षेत्रों में लागू होते हैं। इसका उद्देश्य अनुसूचित सड़कों के किनारे अनियमित विकास को प्रतिबंधित करना और नियंत्रित क्षेत्र के नियोजित विकास को सुनिश्चित करना है। अनुसूचित सड़क अधिनियम की धारा 4 के तहत, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा (ए) किसी भी शहर की सीमा के बाहरी किनारों पर आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर किसी भी क्षेत्र के पूरे या किसी हिस्से को घोषित कर सकती है, या (बी) किसी भी औद्योगिक या आवास

संपत्ति, सार्वजनिक संस्थान या प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक की सीमा के बाहरी किनारों पर दो किलोमीटर की दूरी पर नियंत्रित क्षेत्र होना चाहिए। धारा 4 का डोमेन एक शहर की सीमा के बाहर संचालित होता है। इस प्रकार, स्थानीय क्षेत्र जो 'शहर' के विवरण में आते हैं और नगरपालिका अधिनियम द्वारा शासित होते हैं, अनुसूचित सड़क अधिनियम की धारा 4 संचालित नहीं होगी। अनुसूचित सड़क अधिनियम की धारा 4 के खंड (ए) उप-धारा (1) के अर्थ में 'नियंत्रित क्षेत्र' केवल वह क्षेत्र हो सकता है जो किसी शहर की सीमा के बाहर है। अनुसूचित सड़क अधिनियम की धारा 5 नियंत्रित क्षेत्र को दर्शाने वाली और उसमें निर्दिष्ट करने वाली योजनाएं तैयार करने का प्रावधान करती है

किसी भवन के निर्माण या पुनः निर्माण, सड़कों के लिए भूमि के आवंटन या आरक्षण आदि के लिए प्रतिबंध और शर्तें। अनुसूचित सड़क अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों का उद्देश्य नियंत्रित क्षेत्र में उसी उद्देश्य को प्राप्त करना है जो कि धारा 203 है। अधिनियम एक शहर की नगरपालिका सीमा के भीतर लक्ष्य हासिल करना चाहता है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 203 के प्रावधान अनुसूचित सड़क अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं हैं। इसलिए, अधिनियम की धारा 203 के प्रावधान अनुसूचित सड़क अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हैं, इसलिए लागू रहेंगे। इसलिए, यह मानना होगा कि अनुसूचित सड़क अधिनियम के प्रावधान राज्य सरकार को नगर नियोजन योजना तैयार करने और उसे लागू करने से प्रतिबंधित नहीं करते हैं।

करतार सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 1987 (II) आई.एल.आर. (पंजाब और हरियाणा श्रृंखला) 165 पत्र पेटेंट माननीय श्री न्यायमूर्ति द्वारा पारित आदेश दिनांक 10 जुलाई, 1986 के खिलाफ पत्र पेटेंट के खंड एक्स के तहत अपील

डी. वी. सहगल, सी.डब्ल्यू.पी. 1985 का क्रमांक 3779.

इसलिए प्रार्थना की जाती है कि अपील स्वीकार कर ली जाए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले को रद्द कर दिया जाए और रिट याचिका को जुर्माने सहित खारिज कर दिया जाए।

अपीलकर्ताओं के लिए एन.एस.पवार, सीनियर डी.ए.जी., हरियाणा।

वी.के. बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता (अनिल खेत्र पाल, उनके साथ अधिवक्ता),

उत्तरदाताओं संख्या 1 से 15 के लिए।

प्रतिवादी संख्या 16 के लिए वकील राजेश चौधरी।

आदेश

जी. आर. मजीठिया, जे.

(1) यह निर्णय लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 832 और 1986 का 833का निपटान करेगा।

(2) थानेसर नगर पालिका ने एक विशेष आदेश संख्या 104 द्वारा नगर पालिका की सीमा के अंतर्गत कुछ क्षेत्र को अनिर्मित क्षेत्र घोषित किया। हरियाणा सरकार ने पंजाब मुनिसिपल एक्ट, 1911 की धारा 3 की उप-धारा (18) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 28 जनवरी, 1969 के आदेश के तहत विशेष आदेश संख्या 104 की पुष्टि की। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (संक्षेप में, 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) 2 जुलाई, 1973 के हरियाणा सरकार के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ था। इसने पंजाब को निरस्त कर दिया नगरपालिका अधिनियम, 1911। अधिनियम के लागू होने से पहले, पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 के तहत तैयार की गई योजनाएँ तब तक लागू रहेंगी जब तक कि ये अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न हों। अधिनियम की धारा 203 में थानेसर नगर पालिका को अनिर्मित क्षेत्र के लिए एक टाउन प्लानिंग योजना तैयार करने का आदेश दिया गया, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। उन भूमि मालिकों द्वारा कोई निर्माण गतिविधि नहीं की जा सकती थी जिनकी भूमि विशेष आदेश के अंतर्गत आती थी, क्योंकि भूमि को अनिर्मित क्षेत्र घोषित किया गया था और भवन गतिविधि को नगर नियोजन योजना द्वारा विनियमित किया जाना था। भूस्वामियों ने नगर नियोजन योजना तैयार करने के लिए आवेदन दिया था. थानेसर नगर पालिका ने नगर नियोजन योजना तैयार करने के लिए जिला नगर योजनाकार, कुरूक्षेत्र को सर्वेक्षण योजना और स्वामित्व विवरण प्रस्तुत किया। किसी से पहले अंतिम निर्णय हरियाणा राज्य द्वारा लिया जा सकता है - पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 (इसके बाद इसे 'अनुसूचित' कहा जाएगा) की धारा 4(1) (डी) के तहत 26 सितंबर, 1980 की अधिसूचना के तहत सड़क अधिनियम') ने क्षेत्र को 'नियंत्रित क्षेत्र' घोषित किया। अनुसूचित सड़क अधिनियम के तहत अधिसूचना के परिणामस्वरूप, नगर नियोजन योजना को अंतिम रूप देना रोक दिया गया था। विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या क्षेत्र को अधिनियम की धारा 203 द्वारा विनियमित किया जाना है या अनुसूचित सड़क अधिनियम द्वारा। राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया. जिन भू-स्वामियों की भूमि अनिर्मित क्षेत्र घोषित की गई थी पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 की धारा 3 की उप-धारा (18) के खंड (बी) ने राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र को 'नियंत्रित क्षेत्र' घोषित करने की घोषणा को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी रिट जारी करने के लिए इस न्यायालय का रुख किया। पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा तीन की उपधारा के खंड (बी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी 28 जनवरी 1969 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया

(18) और प्रतिवादी राज्य को परमादेश की रिट के विकल्प में

एक नगर नियोजन योजना बनाएं।

(3) रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी और उन्होंने 28 जनवरी, 1969 की अधिसूचना के तहत घोषित अनिर्मित क्षेत्र के लिए अधिनियम की धारा 203 के तहत एक नगर नियोजन योजना तैयार करने के लिए राज्य को निर्देश देने के लिए एक परमादेश जारी किया था। विद्वान एकल न्यायाधीश के इस आदेश को हरियाणा राज्य और उसके अधिकारियों द्वारा अपील में चुनौती दी गई है।

(4) अपीलकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि एक बार क्षेत्र को अनुसूचित सड़क अधिनियम के तहत नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, तो अधिनियम के तहत एक नगर नियोजन योजना तैयार नहीं की जा सकती है। यह बताया गया कि अनुसूचित सड़क अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अनुरूप एक योजना राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है और रिट याचिकाकर्ता यदि निर्माण गतिविधियों को अंजाम देना चाहते हैं तो उन्हें निदेशालय से अनुमति के लिए आवेदन करना चाहिए।टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा की दर।

(5) अनुसूचित सड़क अधिनियम की धारा 24 राज्य सरकार को नियंत्रित क्षेत्र में शामिल भूमि के उपयोग और विकास पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है। लेकिन यदि राज्य सरकार किसी अन्य कानून के तहत नियंत्रित क्षेत्र में भूमि के विकास के लिए एक विकास योजना तैयार करती है, तो भी योजना को लागू किया जा सकता है, बशर्ते यह अनुसूचित सड़क अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न हो। अनुसूचित सड़क अधिनियम की धारा 24

निम्नानुसार पढ़ता है:

बचत - इस अधिनियम में कुछ भी सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की भूमि अधिग्रहण करने या किसी अन्य कानून के तहत नियंत्रित क्षेत्र में शामिल भूमि के उपयोग और विकास पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। इस अधिनियम के तहत शक्तियों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले दावे को आपसी समझौते से निपटाने की अनुमति देना।

इस खंड का स्पष्ट अध्ययन अन्य अधिनियमों के तहत तैयार नियंत्रित क्षेत्र में शामिल भूमि के विकास के लिए विकास योजनाओं की सुरक्षा करता है। अनुसूचित सड़क अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) में परिकल्पना की गई है कि यह किसी अन्य अधिनियम के तहत की गई कार्रवाइयों को प्रभावित नहीं

करेगा, सिवाय इसके कि जहां अन्य अधिनियम के तहत की गई कार्रवाइयां अनुसूचित सड़क अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत हैं। अनुसूचित सड़क अधिनियम के प्रावधान विभिन्न क्षेत्रों में लागू होते हैं। इसका उद्देश्य अनुसूचित सड़कों के किनारे अनियमित विकास को प्रतिबंधित करना और नियंत्रित क्षेत्र के नियोजित विकास को सुनिश्चित करना है। अनुसूचित सड़क अधिनियम की धारा 4 के तहत, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा (ए) किसी भी शहर की सीमा के बाहरी किनारों पर आठ किलोमीटर की दूरी पर, या (बी) से सटे किसी भी क्षेत्र के पूरे या किसी हिस्से को घोषित कर सकती है।) किसी भी औद्योगिक या आवास संपत्ति, सार्वजनिक संस्थान या प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक की सीमा के बाहरी किनारों पर दो किलोमीटर की दूरी पर एक नियंत्रित क्षेत्र होना चाहिए। धारा 4 का डोमेन एक शहर की सीमा के बाहर संचालित होता है। अनुसूचित सड़क अधिनियम में शहर को परिभाषित नहीं किया गया है। अधिनियम में किसी विशेष परिभाषा के अभाव में हमें सामान्य शब्दकोश अर्थ का सहारा लेना पड़ता है। वेबस्टर की न्यू वर्ल्ड डिक्शनरी में, 'शहर' का अर्थ है, "घरों और निजी और सार्वजनिक भवनों का एक कम या ज्यादा केंद्रित समूह, जो एक गांव से बड़ा लेकिन एक शहर से छोटा है"। अधिकांश स्थानीय क्षेत्र जो कस्बों का निर्माण करते हैं, अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। इस प्रकार, स्थानीय क्षेत्र जो 'शहर' के विवरण में आते हैं और नगरपालिका अधिनियम द्वारा शासित होते हैं, अनुसूचित सड़क अधिनियम की धारा 4 संचालित नहीं होगी। अनुसूचित सड़क अधिनियम की धारा 4 के खंड (ए) उपधारा (1) के अर्थ में 'नियंत्रित क्षेत्र' केवल वह क्षेत्र हो सकता है जो किसी शहर की सीमा के बाहर है। अनुसूचित सड़क अधिनियम की धारा 5 नियंत्रित क्षेत्र को दर्शाने वाली योजना तैयार करने और उसमें किसी भवन के निर्माण या पुन: निर्माण, सड़कों के लिए भूमि के आवंटन या आरक्षण आदि के लिए प्रतिबंध और शर्तों को निर्दिष्ट करने का प्रावधान करती है। धारा 5 के प्रावधान अनुसूचित सड़क अधिनियम का लक्ष्य नियंत्रित क्षेत्र में उसी उद्देश्य को प्राप्त करना है जिसे अधिनियम की धारा 203 के अंतर्गत प्राप्त करना है किसी कस्बे की नगरपालिका सीमा। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 203 के प्रावधान अनुसूचित सड़क अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं हैं। इसलिए, अधिनियम की धारा 203 के प्रावधान अनुसूचित सड़क अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हैं, इसलिए लागू रहेंगे।

(6) हमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में कोई कमजोरी नहीं मिली। हम अपीलों को खारिज करते हैं और पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ देते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया

जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसमीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TraineeJudicial Officer)

कैथल, हरियाणा